66 लाख कीमत का 440 किलो डोडा और चूरा के साथ स्कार्पियो गाड़ी जब्त

नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे तस्करों को चित्तौड़गढ़ पुलिस ने दबोचा, यू-टर्न के प्रयास में बरसाती नाले में पलट गई थी बदमाशों की गाड़ी

जयपुर/चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक स्कोर्पियो से 440 किलो 695 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। जप्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 66 लाख रुपए है। नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे तस्करों का पीछा करने पर बरसाती नाले में पलटी खाने के बाद स्कॉर्पियो में सवार दोनों तस्कर अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि जिले के सभ्जी थानाधिकारियों को अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के निर्देश दिए गए है। इसी क्रम में एएसपी सरीता सिंह व डीएसपी गंगरार प्रभुलाल कुमावत के निर्देशन एवं एसएचओ राशमी श्यामराज सिंह के नेतृत्व में हैड कांस्टेबल गोपाल लाल, कांस्टेबल रमेश विश्नोई, विनोद कुमार, दिनेश सिहाग, चतरदान, दीपक कुमार व राकेश कुमार द्वारा थाना क्षेत्र के गांव लसाडिया कला की सरहद में नाकाबन्दी की जा रही थी।

इसी दौरान पहुँना की तरफ से एक स्कॉपियो आती हुई नजर आई, जिसे टीम ने हाथ का इशारा कर रुकवाने का प्रयास किया तो नाकाबन्दी तोड़ते हुए चालक गाड़ी को तेज गति से गंगापुर की तरफ भगा ले गया। पुलिस टीम ने लगातार पीछा किया, लसाडिया कला गांव में स्कॉर्पियो के आगे पुलिस की गाड़ी लगा दी। इस पर स्कोर्पियो चालक ने अपनी गाड़ी को यूटर्न कर भगाने का प्रयास किया, जिससे स्कॉर्पियो बरसाती नाले में गिर कर पलटी खा गई। जिसमे से दो व्यक्ति उतर कर अंधेरे का फायदा उठा जंगलो की तरफ भाग गए।

टीम ने काफी प्रयास किया, लेकिन दोनों ही तस्कर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो उसमें 23 प्लास्टिक के कट्टे रखे हुए थे, जिसमे कुल 440 किलो 695 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भरा था। स्कॉर्पियो गाडी व अवैध अफीम डोडा चूरा जप्त कर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में थाना राशमी के कांस्टेबल विनोद कुमार व दीपक कुमार का विशेष योगदान रहा।

चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक स्कोर्पियो से 440 किलो 695 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है।

■ अंधेरे का फायदा उठाकर दो तस्कर फरार हो गए, चित्तौड़गढ़ पुलिस उनकी तलाश में जुटी

राइजिंग राजस्थान में हुए एम.ओ.यू. को धरातल पर उतारें : वैभव गालरिया

''सभी प्राधिकरण और न्यास अपने-अपने जिला कलक्टर से समन्वय करके निवेशकों से सम्पर्क स्थापित करें और भूमि चिह्निकरण, भू-आवंटन के प्रकरण तुरंत निस्तारित करें''

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने गुरूवार को राइजिंग राजस्थान समिट में हुए एम.ओ.यू. से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

जयपुर। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने गुरूवार को राइजिंग राजस्थान समिट में हुए एम.ओ.यू. से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के एमओयू को धरातल पर लाने के लिए सभी प्राधिकरण और न्यास अपने अपने जिले के जिला कलक्टर से समन्वय कर निवेशकों के साथ सम्पर्क स्थापित करें और भूमि के चिह्निकरण, भू आवंटन आदि प्रकरणों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

बैठक में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा भी की गई। गालरिया ने कहा कि विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने इस संबंध में आ रही समस्याओं के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की तथा उचित दिशा निर्देश दिये। उन्होंने विधानसभा प्रश्नों के उत्तर, लम्बित लाइट्स प्रकरण, सम्पर्क पोर्टल के प्रकरण, कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण की समीक्षा, रिक्त भूखण्ड एवं लैण्ड बैंक की समीक्षा सहित अन्य बिन्दुओं के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की।

उन्होंने जेडीए में लम्बित न्यायिक प्रकरणों में की संख्या कमी की सराहना की और कहा जिलों में भी लम्बित प्रकरणों को शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने जिलों में अवमानना एवं निर्णय की पालना से शेष प्रकरणों के बारे में भी जिलाधिकारियों से चर्चा की और उनके त्वरित निपटान के लिए निर्देशित किया।

प्रमुख शासन सचिव ने विभाग के कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण व प्रशिक्षणों की स्थिति के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि समस्त कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या के सापेक्ष कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण व प्रशिक्षण शत प्रतिशत किया जाए।

उन्होंने रिक्त भूखण्ड एवं लैण्ड बैंक की समीक्षा करते हुए कहा कि विक्रय योग्य भूमि को सूचिबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण एवं न्यास के स्वामित्व वाली भूमियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सतत रूप से इन भूमियों की निगरानी की जाए तथा अतिक्रमणों का चिह्निकरण कर उन्हें हटाने की तत्काल कार्रवाई की जाए।

बैठक में जेडीए आयुक्त आनन्दी, उपशासन सचिव द्वितीय राकेश कुमार गुप्ता, उप शासन सचिव तृतीय राकेश कुमार, राजस्थान आवासन मण्डल सचिव डॉ. अनिल पालीवाल, मुख्य अभियंता यूडीएच अशोक चौधरी तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला विकास प्राधिकरणों व जिला विकास न्यासों के अधिकारियों ने वीसी के जरिये बैठक में भाग लिया।

राजस्थान की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में विकास कार्यों को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने भजनलाल शर्मा ने कृषक हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषकों के कल्याण एवं कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और उनका जीवन खुशहाल बनाने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढ्राचे को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की राज्य बजट घोषणा की अनुपालना में प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में 27 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की मंजूरी दी है।

इन कार्यों में कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) बीकानेर में 3.08 करोड़ रुपये एवं कृषि उपज मंडी समिति (विशिष्ट श्रेणी) अलवर में 5.40 करोड़ रुपये के नवीन निर्माण कार्य, कृषि उपज मंडी समिति (फल एवं सब्जी) जयपुर के जमवारामगढ़ सब यार्ड में 9.02 करोड़ रुपये के नवीन निर्माण एवं विद्युत कार्य तथा कृषि उपज मंडी समिति (विशिष्ट श्रेणी) बारां में 9.49 करोड़ रुपये के नवीन निर्माण, विद्युत व ऑयल टेस्टिंग मशीन के कार्य शामिल हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में कृषि आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने योग के साथ की नववर्ष की शुरूआत

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष 2025 की शुरुआत सकारात्मकता और स्वास्थ्य के संकल्प के साथ की। उन्होंने वर्ष की शुरुआत अपनी टीम के साथ योग सत्र से की। शर्मा ने कहा कि योग एक अभ्यास होने के साथ-साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर पहला कदम है। योगाभ्यास से मिली ऊर्जा से हम सब मिलकर राजस्थान के उत्थान के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आव्हान किया कि नए साल में सभी मिलकर स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान के निर्माण में योगदान दें।

■ सभी मिलकर स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान के निर्माण में दें योगदान : भजनलाल शर्मा

युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में भागीदारी निभाएं : राज्यपाल

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरूवार को लातूर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 59 वें देवगिरी राज्य सम्मेलन का शुभारंभ किया।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के लातूर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 59 वें देवगिरी राज्य सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं का आव्हान किया कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत से जुड़कर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभाएं।

बागडे ने कहा कि देश की देश के जीडीपी में लगभग 34 प्रतिशत योगदान युवाओं का है। एबीवीपी 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ राष्ट्र के विकास में विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को जोड़ने की पहल करे। उन्होंने इस संगठन के जरिए गांव और शहर का भेद मिटाते हुए देश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करने पर जोर दिया।

राज्यपाल ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए सब मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जब युवा अपने विचारों और ऊर्जा का योगदान राष्ट्र की समृद्धि में करेगा तो निश्चित ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे।

बागडे ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक जड़ों को खोखला करने के लिए मैकाले द्वारा देश की शिक्षा पद्धित को बदला गया। होना तो यह चाहिए था कि देश में 15 अगस्त, 1947 को जिस तरह से झंडा बदला गया था वैसा ही शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम आज भी इसका परिणाम भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1986 में जो शिक्षा नीति बनी, उसके 34 वर्ष बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण ऐतिहासिक पहल है। इसमें भारतीयता को सर्वोच्च महत्व दिया गया। यह नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार की गयी है। यह स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली है।

राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परम्परा के साथ आधुनिक सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर इसे तैयार करने की चर्चा करते हुए कहा कि युवाओं को राष्ट्र विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि इस संगठन की बलराज मधोक जी की पहल पर इसलिए स्थापना हुई कि इससे राष्ट्रोत्थान के लिए कार्य किया जा सके। उन्होंने देवगिरी राज्य सम्मेलन को महत्वपूर्ण बताया।

'आदेश की पालना करो वरना कुर्की-गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकते हैं'

■ लाइनमैन को बकाया वेतन और पुनः सेवा में लेने को लेकर लेबर कोर्ट द्वारा दिए गए अवार्ड फैसले की पालना नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने फटकार लगाई

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने लाइन मैन को बकाया वेतन और उसे पुनः सेवा में लेने को लेकर लेबर कोर्ट के अवार्ड की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने करौली नगर परिषद के आयुक्त को कहा है कि वे 13 जनवरी तक अवार्ड की पालना कराए। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि अवार्ड की पालना नहीं की गई तो उनके ऑफिस की कुर्की होने के साथ ही उनके स्वयं के गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। वहीं अदालत ने स्वायत्त शासन निदेशक और नगर परिषद आयुक्त से आदेश की पालना को लेकर शपथ पत्र पेश करने को कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश दिलीप सिंह गुर्जर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता एक मई, 2007 से पांच अक्टूबर, 2020 तक नगर परिषद, करौली में लाइनमैन के तौर पर कार्यरत था। इसके बाद उसे मौखिक आदेश से हटा दिया गया और वेतन भी जारी नहीं किया। इस पर उसके स्थानीय लेबर कोर्ट में याचिका पेश की। लेबर कोर्ट ने 20 सितंबर, 2022 को अवार्ड जारी कर याचिकाकर्ता को बकाया वेतन का चालीस फीसदी राशि का भुगतान और उसे पुनः सेवा में लेने को कहा था। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने अवार्ड की पालना नहीं की। वहीं लेबर कोर्ट ने भी गत 4 मार्च को अवार्ड की पालना के लिए उसे राज्य सरकार को भेजा, लेकिन आदेश की पालना नहीं की गई।

इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने भी गत 10 मई को अवार्ड की पालना के आदेश दिए थे, लेकिन विभाग ने पालना नहीं की। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए अवार्ड की पालना नहीं करने पर ऑफिस कुर्क करने और अधिकारी के गिरफ्तारी वारंट जारी करने की चेतावनी दी है।

विशेषज्ञों की राय से जिलों पर हुआ फैसला : मदन दिलावर

■ शिक्षा मंत्री ने कहा कि ''कांग्रेस पार्टी, भजनलाल सरकार से घबराई''

जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा उलूल-जुलूल बयान देते रहते हैं। इनकी सरकार में जब जिले बनाने की चर्चा आयी तो अपना दिमाग नहीं लगाया। ना किसी एक्सपर्ट से राय ली। केवल राजनैतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने एक-एक विधानसभा क्षेत्र का भी जिला बना दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्सपर्ट से राय ली और कमेटी बनाई, फिर मंत्रीमण्डलीय उपसमिति बनाई, सबसे विचार-विमर्ष करने के बाद जो सलाह आई, उसके आधार पर नवीन जिलों पर फैसला लिया गया। जो कि पूर्ण रूप से सही है। कांग्रेस यह फैसला पचा नहीं पा रही है। इसलिए ज्यादा उछल-कूद कर रही है। उपचुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली है। इसलिए बेचारे उलूल-जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काम और फैसले लेने की स्पीड से कांग्रेस घबराई हुई है। उनको लग रहा है कि आगामी 100 साल तक तो शायद कांग्रेस वापस नहीं आ पाएगी और इसलिए जिस प्रकार से मछली को पानी के बाहर निकाल देते है और वो तड़पती रहती है। उसी प्रकार से डोटासरा तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोटासरा तड़प रहे हैं कि कैसे माल खाएं, कैसे भ्रष्टाचार करें, कैसे लूटपाट करें।

कांग्रेस को नहीं पच रहे हैं भजनलाल सरकार के शानदार काम : राजेन्द्र राठौड़

■ राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए जनभावनाओं से खेलना बंद करे कांग्रेस

जयपुर, (कासं)। वरिष्ठ भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए जनभावनाओं से खेलना बंद करे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के काम कांग्रेस को पच नहीं पा रहे। असल में सरकार के शानदार काम के बाद मुद्दा विहीन कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, इसलिए ये मुद्दा तलाशने में लगे हैं।

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल में आनन-फानन के अंदर रामलुभाया कमेटी की अभिशषांओं को दरकिनार करके जिस प्रकार 17 जिले बनाए, तीन संभाग बनाए, उसमें ना आवश्यक वित्तीय प्रावधान किया, ना दूरियां देखीं, ना यह देखा कि मानव संसाधन कहां से आएगा। बस चुनावी वैतरणी पार करने के लिए एक के बाद एक जिलों की घोषणा कर दी। अब मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति और उप मंत्रिमंडलीय समिति के सिफारिश के बाद इनको निरस्त किया। असल में सरकार के शानदार काम के बाद मुद्दा विहीन कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा।

राठौड़ ने कहा कि शायद कांग्रेस को ये बात अच्छी नहीं लगी कि राजस्थान निर्माण के बाद पहली बार 1 लाख 11 हजार करोड़ के आधारभूत संरचनाओं से जुड़े हुए कामों की एक साथ स्वीकृति, शिलान्यास या उद्घाटन हुआ। कांग्रेस शायद इस बात को भी नहीं पचा पा रही कि जिन मुद्दों को लेकर वो लगातार राजनीति करती रही, चाहे ईआरसीपी का हो या यमुना जल का हो, वो मुद्दे अब जनता के सामने व्यावहारिक तौर पर हल होते नजर आ रहे हैं। अब नौजवान को उसके हक मिल रहा है। पहली बार नौजवानों का नौकरियों का कैलेंडर एक साथ जारी किया गया है।लगातार अलग-अलग नीतिगत निर्णय पारदर्शिता के साथ लिए जा रहे हैं। ये सारी बातें कांग्रेस को पच नहीं रही इसलिए जनता के बीच में जिलों के पुनर्गठन को लेकर बेसिर-पैर की बातें कर रहे हैं, लेकिन जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है।

देवनानी आज विधानसभा प्रश्नों के लम्बित जवाबों की समीक्षा करेंगे

■ मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों से लम्बित प्रकरणों पर चर्चा होगी

जयपुर, (कासं)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शुक्रवार को दोपहर तीन बजे विधानसभा में प्रदेश के मुख्य सचिव सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवगण से विधान सभा में विधायकों द्वारा लगाये गये प्रश्नों के जवाबों के लम्बित प्रकरणों पर जानकारी लेंगे।

देवनानी ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप विधायकों द्वारा राज्य सरकार से जनहित के विषयों पर प्रश्न एवं प्रस्तावों के माध्यम से जानकारी मांगी जाती है। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा विधानसभा को इनकी जानकारी समय पर प्राप्त नहीं होने से इनकी सार्थकता समाप्त हो जाती है। विधानसभा को राज्य सरकार के विभागों से प्रश्नों का जवाब प्राप्त नहीं होने से विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों का भी उल्लंघन होता है।

विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत को सभी विभागों के सचिव स्तर के अधिकारीगण सहित बैठक में भाग लेने के लिए पत्र प्रेषित किया है। पत्र में सोलहवीं विधानसभा के आगामी संभावित सत्र से पहले के प्रश्नों, प्रस्तावों और आश्वासनों के जवाबों के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने के लिए कहा गया है।

जयपुर बुकमार्क 30 जनवरी से

जयपुर। अनुवाद एवं अधिकारों (ट्रांसलेशन एंड राइट्स) पर फोकस करते हुए जयपुर बुकमार्क (जेबीएम) लगातार 12वें साल दक्षिण एशिया में प्रकाशन के अग्रणी प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार है। आगामी 30 जनवरी से 3 फरवरी तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के साथ-साथ चलने वाला जेबीएम कई तरह के जीवंत विमर्श का केंद्र बनेगा।

यह सम्मेलन अनुवाद की ताकत एवं क्षमता को खुलकर सभी के समक्ष रखेगा। साथ ही इस दौरान एक व्यापक राइट्स कैटलॉग भी जारी किया जाएगा, जिसे वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें 31 प्रमुख प्रकाशकों द्वारा 10 भारतीय भाषाओं की 51 रचनाओं को शामिल किया गया है। सम्मेलन के दौरान 'प्रकाशन के क्षेत्र में एआई', 'गेम्स के माध्यम से कहानी कहने के नए तरीके' और 'बच्चों की पुस्तकों में समावेश की समझ' जैसे विषय सामने आएंगे।

वर्षा जल सहेजने की परम्परा को पुनर्जीवित करेगा ''कर्मभूमि से मातृभूमि'' अभियान

गांवों को जल आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्ती पहल

■ भामाशाह व प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से बदलेंगे राजस्थान में भूजल के हालात : मुख्यमंत्री

■ सतही जल की एक-एक बूंद के संचय, संग्रहण एवं पुर्नभरण पर फोकस रहेगा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वर्षाजल सहेजने की परम्परा को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने में महती भूमिका निभाने जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं का निर्माण करवाने जा रही है।

यह अभियान जल संचयन में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अनूठी संकल्पना कैच द रेन से प्रेरित है। गत अक्टूबर माह में सूरत में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने 'जन्मभूमि से कर्मभूमि-जल संचय-जनभागीदारी-जनआंदोलन' कार्यक्रम की रूपरेखा रखी थी। शुरुआती स्तर पर इस अभियान के अंतर्गत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनूं और जयपुर जिलों में कार्य प्रारम्भ किए गए हैं।

अन्य प्रदेशों को अपनी कर्मभूमि बना चुके प्रवासी राजस्थानी व्यवसायी, उद्यमी एवं अन्य अग्रणी लोगों को जोड़कर भावनात्मक रूप से प्रेरित करते हुए राजस्थान में अपने गांव में जल संरक्षण गतिविधियों में शामिल होकर वर्षा जल संचयन और जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्थानीय भामाशाहों के अलावा प्रवासी राजस्थानी क्राउड फंडिंग के माध्यम से और कॉरपोरेट्स सीएसआर फंडिंग के माध्यम से इस अभियान के अंतर्गत रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण 216 पंचायत समितियां यानी प्रदेश का 72 प्रतिशत भाग अतिदोहित श्रेणी में आ गया है, जिसमें भूजल की गुणवत्ता भी खराब हुई है।

इस अभियान से भूजल स्तर में गिरावट रोकने के साथ-साथ घरेलू उपयोग तथा कृषि कार्यों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। अभियान में पर्यावरण अनुकूल रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं से व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल और भाप बन कर उड जाने वाले सतही जल की एक-एक बूंद के संचय, संग्रहण एवं पुर्नभरण पर फोकस किया जाएगा।